renegotiate PPAs on the basis of various Electricity Acts/notifications and guidelines in vogue. Internal rate of return of the project is not specified by the Government of India and hence not used as guidelines for CEA's project evaluation.

(b) Yes Sir. the promoters, M/s Hinduja National Power Corporation Ltd. have conveyed concern of their partners about the escalating casts of developing the project and the protracted delays in bringing the project to finalisation.

(c) As per techno-economic clearance given by CEA, the commercial operation date of Unit I/II of the project is likely to be 38/44 months from the date of financial closure. The sale rate of Power shall be governed by the completed capital cost, approved financial package and the PPA entered into between APSEB & the developer.

Oman Oil Pipeline Gas Project

684. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY:
DR. Y. LAKSHMI PRASAD:
SHRI K. RAHMAN KHAN:
PROF. NAUNIHAL SINGH:
SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:
SHRI BHAGABAN MAJHI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Oman Oil Pipeline Gas Project has been shelved;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether Government propose to re-examine the project;

(d) whether Government have any other alternative; and

(e) the steps being taken to meet the target of LPG connections to 20 lakh consumer's in 1996-97?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SH. T. R. BAALU): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) GAIL and Oman Oil Company are setting up a joint working group to expedite the feasibility study for the project.

(d) Import of gas from Iran and import of LNG are being persued as alternatives.

(e) The steps taken include higher domestic production as well as higher imports of LPG.

Gas Turbine Plant in Manipur

685. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Manipur Government has proposed a gas turbine plant at Jiriban to the Central Government;

(b) if so, what is its scapacity;

(c) whether Government have considered the proposal; and

(d) whether the proposal is feasible; if so, by when it is likely to commence?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

ग्रामीण भूमिहीन और आवासहीन श्रमिकों के लिये मकान उपलब्ध कराना

686. श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर गजरात में केन्द्र सरकार

द्वारा ग्रामीण आवास हेतु प्रायोजित योजना के अन्तर्गत ग्रामीण भूमिहीन और आवासहीन श्रमिकों के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या रहे;

(ग) क्या ऐसे भूमिहीन श्रमिकों को भूमि और मकान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों हेतु कोई वितीय सहायता मंजूर की गई है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार आबंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, 1991 की जनगणना के अनुसार, देश में ग्रामीण आवासों की कमी 13.72 मिलियन थी जिसमें से गुजरात में ही ग्रामीण आवासों की कमी 2.65 लाख थी।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रायोजित इंदिरा आवास योजना के तहत, राज्य सरकारों के लिए चालू वर्ष के दौरान भूमिहीन एवं आवासहीन श्रमिकों सहित ग्रामीण गरीबों हेतु आवासों के निर्माण के लिए 1140.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। चालू वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्यवार आबंटन विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)।

(घ) प्रश्न नहीं उठता

विवरण

1996-97 के दौरान इंदिरा आवास योजना के तहत केन्द्रीय आबंटन

रुपये लाख में

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	8870.30
2.	अरूणाचल प्रदेश	79.71
3.	असम	2919.68
4.	बिहार	17398.92
5.	गोवा	86.12
6.	गुजरात	3255.70
7.	हरियाणा	782.14
8.	हिमाचल प्रदेश	273.65
9.	जम्मू व कश्मीर	556.07
10.	कर्नाटक	5956.29
11.	केरल	2167.06
12.	मध्य प्रदेश	11240.56
13.	महाराष्ट्र	9669.47
14.	मणीपुर	102.16
15.	मेघालय	119.54
16.	मिजोरम	50.36
17.	नागालैंड	128.23
18	उड़ीसा	7195.91
19.	पंजाब	556.24
20.	राजस्थान	4670.13
21.	सिक्किम	46.65
22.	तमिलनाडु	8018.92
23.	त्रिपुरा	132.82
24.	उत्तर प्रदेश	21616.11
25.	पश्चिम बंगाल	7949.67
26.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	47.17
27.	दादर व नगर हवेली	25.61
28.	दमन व द्वीव	15.08
29.	लक्षद्वीप	23.65
30.	पांडीचेरी	46.18
	कुल	114000.00